



MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

Peer Reviewed International Multilingual Research Journal

VIDYAWARTA

Issue-39, Vol-05, July to Sept. 2021



Editor
Dr. Bapu G. Gholap

ग्रामीण कृषि साख के गैर संस्थागत संस्थाओं का अध्ययन गाँव चित्तौड़ा जनपद मुजफ्फरनगर (उ०प्र०) के विशेष सन्दर्भ में

डॉ० प्रमोद कुमार

असि० प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),

राजकीय महाविद्यालय, चिन्पालीसौड़, उत्तरकाशी
(उत्तराखण्ड)

प्रस्तावना —

ग्रामीण साख के अन्तर्गत कृषि साख का दायरा बहुत विस्तृत है। यह इतना विस्तृत है कि प्रायः कृषि साख को ही ग्रामीण साख का पर्यायवाची मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्भरता कृषि पर है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लगभग दो — तिहाई लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।

कृषि एक व्यवसाय है और प्रत्येक व्यवसाय के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। अतः अन्य व्यवसायों की भाँति कृषि को सफल बनाने के लिए सस्ती एवं पर्याप्त साख की आवश्यकता है। भारतीय किसान के लिए इसकी आवश्यकता और भी बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास खेत आर्थिक जोत के नहीं है। उसकी आय इतनी कम होती है कि भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए या नई भूमि खरीदने के लिए रूपया बचाना तो दूर रहा वह दैनिक कार्यों के लिए भी ऋण लेकर ही काम चलाता है।

कृषि वित्त की समस्या वाणिज्य और उद्योग के लिए वित्त की समस्या से भिन्न है। वाणिज्य और उद्योग अपेक्षाकृत संगठित व्यवस्था है और इनकी वित्त की मांग उत्पादक कार्यों के लिए ही होती है। यही कारण है कि इनकी वित्त की मांग को पूरा करने

के लिए बहुत पहले ही विभिन्न देशों में बैंकों और औद्योगिक वित्त की विशिष्ट संस्थाओं का विकास हुआ है। कृषि अपेक्षाकृत असंगठित व्यवसाय है इसकी सफलता तथा असफलता बहुत कुछ मौसम पर निर्भर करती है। इसके अलावा किसानों द्वारा लिये जाने वाले ऋणों में स्पष्ट रूप से उत्पादक और अनुपादक में भेद कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए बैंकों में खेती के लिए या उससे सम्बन्धित दूसरे कार्यों के लिए ऋण देने में प्रायः दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है और लम्बे अर्से तक किसान ऋण के लिए मुख्य रूप से साहूकार व महाजनों पर निर्भर रहे हैं।
कृषि वित्त का अर्थ व परिभाषा—

कृषि वित्त से आशय निवेश किये जाने वाले धन की उस राशि से है जो कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सहायक होती है। उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया ऋण एवं उपभोग ऋण कृषकों की दक्षता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं किन्तु कृषकों पर ऋण का इतना अधिक भार होता है कि बुल्फ समिति ने कहा है कि “भारतीय किसान ऋण के रूप में जन्म लेता है, अपने जीवन भर ऋणी बना रहता है और ऋणी रह कर ही मर जाता है।”

अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण के अनुसार —

‘विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जो कृषि साख वर्तमान समय में उत्पादन की जाती है वह अपर्याप्त है व उचित प्रकार की नहीं है तथा आवश्यकता की कसौटी को ध्यान में रखते हुए प्रायः सभी व्यक्तियों तक पहुँचाने में असफल रहती है।’

ग्रामीण साख सर्वेक्षण के अनुसार —

‘कृषि की वह साख जिसकी उसे कृषि कार्यों को पूर्ण करने में आवश्यकता होती है। कृषि वित्त या साख के अन्तर्गत आती है।’

कृषि वित्त की आवश्यकता —

कृषकों की सामान्य वित्तीय आवश्यकताएँ निकलसन के अनुसार निम्न हैं।

‘बीज खाद आदि खरीदने के लिए कृषि व्यय, पशुओं, औजारों तथा कच्चे माल की खरीद, नई भूमि लेने के लिए या भूमि सुधार, सिंचाई व्यवस्था तथा वृक्षारोपण के लिए, पुराना ऋण चुकाने के लिए

Impact of Covid-19 Pandemic on School Education in India

Dr. Pramod Kumar

Assistant Professor (Economics), Govt. Degree College, Chinyali Saur, Uttarkashi

Abstract

No One would guessed that a virus like Covid-19 would come and without differentiating, it will alter the lifestyle of people. Due to Covid-19 many changes come to our world and it took some time for everyone to adopt the new normal. The Covid-19 impact was everywhere, which resulted in the closure of school and other educational institutions. Initially most governments have decided to temporarily later it was reopened for a few grades, which increased the number of infection rate and then closed again.

Though school is closed, students are attending their classes through various education initiatives like online classroom- whatsapp, zoom and Google meet. Though it is a good thing happening on the other side, there are lots of students who did not won the resources to attend the online classes suffer a lot of many students are struggling to obtain the gadgets required for online class.

Teachers who are all experts in Blackboard chalk books and classroom teaching, but they are adopting the new methods and handling it like a pro to aid negative side many teachers are looking for a alternative job to support their families.

Introduction

The corona virus pandemic (2019– 20) began in mid- December 2019 in the city of Wuhan in central China as a result of infection by a new type of corona virus (2019- nCoV). Many people started getting pneumonia without any reason and it was observed that most of the affected people sell fish and also trade in live animals in Wuhan Sea Food Market. Chinese scientists later identified a new strain of corona virus given the preliminary designation 2019- nCoV. This new virus was found to have at least 70 percent of the same genome sequence as that found in SARS- Corona virus. With the development of a specific diagnostic PCR test to detect infection, many cases were confirmed in people who were directly associated with the market and the virus was detected even in people who were not directly associated with the market. Earlier it was not clear whether this virus was as serious or lethal as SARS or not.

To prevent the corona virus pandemic in India, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, ordered a lockdown of the entire country for 21 days on 24 March.

1. This decision was preceded by a 14-hour public curfew on 22 March.
2. While addressing the nation at 10 am on April 14, Prime Minister Shri Narendra Modi decided to extend the lockdown period till May 3 and said that the rules will be more strict in the next one week.
3. Modi ji also said that where new cases do not emerge, some relaxation will be given
4. On 17 May, the Home Ministry announced the extension of the lockdown till 31 May.
5. On May 30, the fifth phase of lockdown was announced across the country.
6. Lockdown 2020 due to corona virus in India

COVID - 19 Lockdown in India.

Phase First: 25March 2020 to 14 April 2020 (21 days)

Second Phase: 15 April 2020 to 3 May 2020 (19 days)

Third Phase: 4 May 2020 to 17 May 2020 (14 days)

Fourth Phase: 18 May 2020 to 31 May 2020 (14 days)

Fifth Phase: 1June 2020 to 30 June 2020 (30 days)